जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 20 संख्याः 141 प्रभात जालोर, गुरुवार 28 अगस्त, 2025 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

'क्या मोदी गत कुछ समय से राष्ट्रपति ट्रंप का फोन जान बूझकर नहीं उठा रहे?'

जर्मन समाचार पत्र एफ. ए. जेड. में प्रकाशित इस खबर से यह तो स्पष्ट जरूर हुआ कि, प्रधान मंत्री मोदी व राष्ट्रपति ट्रंप के बीच नाराज़गी का दौर जारी है और कटुता में तब्दील हो रहा है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 अगस्त। जर्मन अखबार के एक दावे को लेकर जानकार हलकों में संदेह जताया जा रहा है जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल के सप्ताहों में अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की चार फोन कॉल्स की उपेक्षा की, और अब पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव की एक पोस्ट ने इस संदेह को और गहरा कर दिया है।

पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव ने एक्स पर लिखा कि, "यह धारणा कि पीएम मोदी ने ट्रंप की कॉल्स (ट्रंप के कई प्रयासों के बावजूद) जानबूझकर नहीं लीं, एक विदेशी रिपोर्ट पर आधारित है और भारतीय सूत्रों या अन्य मीडिया संस्थानों ने इसकी पुष्टि नहीं की है।" यह पोस्ट उस दिन आई जब फ्रैंकफर्टर ऐल्गेमाइन ज़ाइटुंग (एफएज़ैड) की रिपोर्ट ने भारत में

- पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव के अनुसार, इस खबर की पुष्टी कोई भी नहीं कर रहा है। साथ ही, किसी राष्ट्राध्यक्ष का फोन नहीं उठाना, प्रधान मंत्री के काम करने के तरीके से मेल नहीं खाता।
- साथ ही, यह भी चलन काफी काम में ले रही है भारत सरकार और अब विदेशी मीडिया का खूब खुलकर उपयोग कर रही है, अपना पक्ष जनता के सामने रखने के लिए। क्योंकि विदेशी अखबार द्वारा प्रस्तुत जानकारी को जनता, बिना ज्यादा सवाल किए, स्वीकार कर लेती है। इसका एक उदाहरण, चीफ ऑफ डिफैंस स्टाफ द्वारा ब्लूमबर्ग न्यूज एजेंसी को ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिया गया इंटरव्यू है, जिसमें पहली बार भारत सरकार ने परोक्ष रूप से स्वीकार किया कि, भारत को कुछ लड़ाकू विमान का नुकसान हुआ था, पाकिस्तान के खिलाफ किए गए हवाई हमले में।
- एक वरिष्ठ पत्रकार ने इस संदर्भ में कटाक्ष किया कि,, इस संदर्भ में कि, अगली बार ट्रंप फोन करें तो, मोदी को "ऑटो रिप्लाय" (वॉयस मेल) का उपयोग करना चाहिए, जहां ट्रंप को यह मैसेज मिले, मैं इस वक्त शी व पुतिन के साथ, कार में यात्रा पर हूं। कृपया आप अपना मैसेज "बीप" के बाद में रिकॉर्ड करा दें।"

हलचल मचा दी।

राव ने लिखा "मैं उन अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स को लेकर संदेह में रहती हूं जिनका समर्थन कई स्रोतों से नहीं होता, खासकर जब बात जटिल कूटनीतिक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कोटा जिले में गैर प्रदूषणकारी उद्योग लगेंगे

जयपुर, 27 अगस्त। प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भूमि आवंटन के दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री शर्मा ने कोटा जिले में गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए कनवास तहसील के ग्राम ढोटी में कुल 22.78 हैक्टेयर भूमि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह भूमि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको) को आवंटित की गई है। मुख्यमंत्री के इस

- मुख्यमंत्री ने कनवास में 22 हैक्टेयर भूमि रीको को देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी।

निर्णय से प्रदेश में औद्योगिक और आधारभूत संरचना का विकास होगा एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में वृद्धि भी होगी। शर्मा ने जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क के निर्माण के लिए कुल 101.97 हैक्टयर राजकीय भूमि के आवंटन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। यह भूमि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की मांग के आधार पर संबंधित जिला कलक्टर के प्रस्ताव पर भारत-पाक सीमा के समानान्तर सड़क निर्माण के संरेखण से संबंधित हैं।

भारत के व्यापारी अमेरिका की छोटी-मोटी रियायतों के कुछ ज्यादा ही आदी हो गए थे

और, अब भारी टैरिफ वृद्धि से इन व्यापारियों की वाकई में पैरो तले जमीन खिसक गई है

- सुकुमार साह -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 27 अगस्त। किसी भी पैमाने से देखें, ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत पर टैरिफ़ (आयात शुल्क) दोगुना करना केवल आर्थिक खेल नहीं है, बल्कि दबाव बनाने वाली कूटनीति है। भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाकर वॉशिंगटन ने नई दिल्ली को इस हकीकत से रूबरू कराया कि उसका निर्यात तंत्र कितना नाज़ुक है और उसमें रणनीतिक विविधता लाना कितनी ज़रूरी है।

आंकड़े डराने वाले हैं। भारत का आधे से ज़्यादा निर्यात लगभग 48 अरब डॉलर का – अब अचानक प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गया है। भारतीय उत्पाद अब वियतनाम, बांग्लादेश और मैक्सिको जैसे देशों के मुकाबले 30-35 प्रतिशत महंगे हो गए हैं। फैडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (एफ आई ई ओ) इसे पूरी तरह चौंकाने वाला बताया

- भारत के व्यापारी, अमेरिका के मार्केट से इतने खुश थे, कि, यूरोप, अफ्रीका, लेटिन अमेरिका के मार्केट की ओर ध्यान नहीं के बराबर ही दिया।
- अब वियतनाम, बंगलादेश, मैक्सिको प्रतिस्पर्धी के रूप में भारत का स्थान लेने को तैयार व तत्पर हैं।
- भारत के लिए भारी टैरिफ के कारण उत्पन्न संकट, एक चुनौती है, और सुअवसर भी, अगर भारत वैकल्पिक मार्केट विकसित कर लेता है, तो उसकी इकॉनमी, कभी भी भविष्य में एक देश पर आश्रित नहीं रहेगी, बल्कि स्वस्थ और मजबूत सिस्टम का अंग बनेगी।

और चेतावनी दी कि यह भारत के सबसे बड़े बाज़ार में उसके निर्यात के लिए मौत की घंटी हो सकता है।

इन आंकड़ों के पीछे एक गहरी कहानी है: भारत की नाज़ुक व्यापारिक सुविधाओं पर निर्भरता। दशकों से भारतीय निर्यातक – खासकर कपड़ा, हीरे जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान और समुद्री उत्पादों वाले अमेरिकी खरीदारों तक पहुंच के कारण फैले है। अब उसी पहुँच अमेरिका ने हथियार बना लिया है। जैसा कि एफ आई ई ओ के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा, जब तक शुल्क 25 प्रतिशत था, निर्यातक झटका सहने की उम्मीद रखते थे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका के रूख में यू टर्न, भारत के साथ ट्रेड डील का संकेत दिया

अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि भारत के साथ वार्ता जारी है और जल्दी ही समाधान निकाल लिया जाएगा

वॉशिंगटन डीसी, 27 अगस्त। अमेरकिा के रुख में अचानक बड़ा ट्विस्ट आया है। बुधवार को भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लागू होने के बाद अमेरिका ने भारत के साथ ट्रेड डील हो जाने का साफ संकेत दिया है। उसने यह भी कहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा भारत से आने वाले सामान पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने के फैसले से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। यह फैसला लागू हो गया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि भारत और अमेरिका अंत में एक समझौता कर लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह तनाव सिर्फ भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने की वजह से नहीं है।

सरकार के सूत्रों का कहना है कि इस तनाव के बावजूद वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच बातचीत जारी है। दोनों पक्ष इसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार इस मामले पर उद्योग जगत के लोगों के साथ लगातार संपर्क में है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक योजना बना रही है।

स्कॉट बेसेंट ने फॉक्स न्यूज से बात करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका

- बुधवार 27 अगस्त से अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर 50 प्रतिशत टैरिफ फैसला लागू हो गया है। ऐसे में अमेरिका के वित्तमंत्री का यह बयान न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि भारतीय निर्यातकों के लिए उम्मीद की किरण भी है।
- स्कॉट बेसेंट ने फॉक्स न्यूज़ के साथ वार्ता में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और मोदी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अंत में हम एक साथ आ जाएंगे।

के रिश्ते बहुत जटिल हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अच्छे संबंध हैं। बेसेंट बोले, यह सिर्फ रूस से तेल खरीदने का मामला नहीं है। उन्होंने बताया कि भारत ने लिबरेशन डे के बाद टैरिफ पर बातचीत शुरू कर दी थी। लेकिन, अभी तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। उन्हें उम्मीद थी कि मई या जून तक समझौता हो जाएगा। लेकिन, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदकर मुनाफा कमा रहा है।

27 अगस्त से भारत से आने वाले सामान पर लगने वाला टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया है। पहले 7 अगस्त को 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया था। अमेरिका का कहना है कि यह कदम भारत द्वारा रूस से कच्चा तेल और सैन्य सामान खरीदने के जवाब में उठाया गया है।

बेसेंट ने कहा कि व्यापार में असंतुलन की वजह से अमेरिका को फायदा है। उन्होंने कहा, मैंने टैरिफ पर बातचीत के दौरान हमेशा कहा है कि अमेरिका एक घाटे वाला देश है। जब व्यापारिक रिश्तों में दरार आती है तो घाटे वाले देश को फायदा होता है। सरप्लस वाले देश को चिंता करनी चाहिए। भारतीय हमें सामान बेच रहे हैं। उनके टैरिफ बहुत ऊंचे हैं और हमारा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'पेपर लीक से प्रभावित अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट क्यों नहीं दी'

जयपुर, 27 अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2025 में पेपर लीक से प्रभावित एसआई भर्ती-2021 के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट नहीं देने पर राज्य के गृह विभाग और आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं के आवेदन स्वीकार कर उन्हें चयन प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश रामगोपाल व अन्य की ओर से दायर

- हाईकोर्ट ने एस आई भर्ती 2025 के संदर्भ में ग्रह विभाग व आरपीएससी से जवाब मांगा।

याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने पुलिस उपनिरीक्षक के 859 पदों के लिए साल 2021 में भर्ती निकाली थी। भर्ती के पेपर लीक होने पर हाईकोर्ट में भर्ती निरस्त कराने के लिए याचिका दायर की गई। जिस पर सुनवाई के दौरान गत 28 जून को राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट को जानकारी दी गई कि भर्ती को फिलहाल रद्द करना जल्दबाजी होगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सीज़फायर के लिए भारत के साथ वार्ता का गवाह भी है ट्रंप के पास

ट्रंप का दावा है कि जब वे मोदी से बात कर रहे थे तब अमेरिका ? के वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक भी वहां थे

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पुराने दोस्त और अब दुश्मन बन चुके डॉनल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चौंकाने वाला दावा किया है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब संघर्ष विराम की घोषणा हुई, उससे कुछ घंटे पहले ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी।

ट्रंप का यह बयान मोदी सरकार के उन दावों के विपरीत है जिनमें कहा गया था कि भारत पर किसी भी विदेशी नेता ने सैन्य कार्रवाई रोकने का दबाव नहीं डाला था।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 28 जुलाई को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई बहस के दौरान स्पष्ट रूप से कहा था कि, "22 अप्रैल से 17 जून के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई।"

एक पूर्व राजनयिक से जब ट्रंप के नए दावे पर टिप्पणी मांगी गई, तो उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, "अब सवाल यह है कि किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं – यही पूरी दुनिया पूछ रही है।"

- ट्रंप ने अमेरिका की तीन घंटे चली वीडियो रिकॉर्डेट कैबिनेट मीटिंग में यह दावा किया तथा भारत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ हुई वार्ता का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया।
- उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने भारत और पाक को धमकाया कि अगर युद्ध नहीं रोका तो इतना ज्यादा टैरिफ लगा दूंगा कि सिर घूम जाएगा।
- भारत सरकार देश की संसद में यह दावा कर चुकी है कि 22 अप्रैल से 17 जून के बीच मोदी और ट्रंप की कोई बात नहीं हुई है। खुद प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संसद में यही कहा है।
- अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में यही सवाल उठ रहा है कि भारत-पाक सीज़फायर के मुद्दे पर किसका भरोसा किया जाए।

ट्रंप का यह ताज़ा बयान तीन घंटे लंबी एक वीडियो रिकॉर्डेड कैबिनेट बैठक के दौरान आया, जिसमें उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने अपने सबसे महंगे लड़ाकू विमानों में से कुछ खो दिए।

उन्होंने कहा: "अगर मुझे राष्ट्रपति नहीं चुना जाता, तो रूस-यूक्रेन युद्ध विश्व युद्ध बन जाता – ठीक वैसे ही जैसे भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रहे थे, अगर मैंने उन्हें नहीं रोका होता।"

इसके बाद ट्रंप ने अपने अनुसार घटनाक्रम का विवरण दिया, "ये थोड़ा अजीब था। मैंने देखा कि वे (भारत-पाकिस्तान) लड़ रहे थे। फिर देखा कि सात जेट मार गिराए गए। मैंने कहा, ये ठीक नहीं है। बहुत सारे जेट ! आप जानते हैं, 150 मिलियन डॉलर के विमान गिराए गए – बहुत सारे। सात, शायद उससे भी ज़्यादा। उन्होंने असली संख्या तो बताई ही नहीं।"

गौरतलब है कि केवल भारत का फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू विमान ही लगभग इतनी कीमत का है। पाकिस्तान के पास मौजूद चीनी -जेएफ17 थंडर और अमेरिकी - एफ16 इससे कहीं सस्ते हैं।

इसके बाद ट्रंप ने कहा: "मैं भारत के एक जबर्दस्त इंसान, मोदी से बात कर रहा था। मैंने पूछा, पाकिस्तान के साथ क्या चल रहा है? फिर मैं पाकिस्तान से व्यापार पर बात कर रहा था। मैंने उनसे भी पूछा, भारत के साथ क्या चल रहा है? और दोनों में बहुत ज्यादा नफरत थी।"

ट्रंप ने कहा, "यह सब बहुत लंबे समय से चल रहा है, कभी अलग-अलग नामों से, सैकड़ों सालों से। मैंने कहा, क्या चल रहा है? मैंने कहा, मैं तुमसे कोई व्यापार नहीं करूंगा। उन्होंने कहा, नहीं-नहीं, हम व्यापार चाहते थे। मैंने कहा, नहीं, कोई व्यापार नहीं होगा। तुम लोग परमाणु युद्ध की ओर जा रहे हो।"

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हैरिटेज व ग्रेटर निगमों के विलय के खिलाफ सुनवाई आज होगी

जयपुर, 27 अगस्त। शहर के हैरिटेज और ग्रेटर नगर निगमों का विलय कर एक नगर निगम गठित करने की अधिसूचना के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आरआर तिवाडी की ओर पेश इस जनहित

- कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आर. आर. तिवाड़ी ने हाईकोर्ट में इस विषय पर जनहित याचिका लगाई है।

याचिका पर गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश केआर श्रीराम और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ सुनवाई करेगी।

याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा और अधिवक्ता सुनील शर्मा ने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग की ओर से गत 27 मार्च को जारी की गई यह अधिसूचना पूरी तरह से मनमानी,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या भारत किसी और के शतरंज के खेल में अनायास एक प्यादा बन गया है?

ट्रंप के लिए भारत पर भारी टैरिफ लगाना केवल "इकोनॉमिकल" (साधारण वित्तीय) निर्णय नहीं है, बल्कि एक सामरिक निर्णय है, चीन, रूस व अमेरिका के "रस्ट बैल्ट" क्षेत्र को एक मैसेज देना है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 अगस्त। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप टैरिफ़ (आयात शुल्क) का सहारा लेते हैं, तो यह केवल अर्थव्यवस्था की वजह से नहीं होता। टैरिफ़ उनका पसंदीदा हथियार है, एक ऐसा औज़ार जिससे वे विरोधियों को दबाते हैं, घरेलू जनता को खुश करते हैं और सहयोगी व दुश्मनों दोनों को अपनी ताक़त दिखाते हैं। वॉशिंगटन के रणनीतिक साझेदार के रुप में भारत का महत्व बढ़ने बावजूद अब इस खेल में भारत एक असहज स्थिति में है। ट्रंप के दंडात्मक शुल्क, भारतीय निर्यात पर 50 प्रतिशत, कुछ उद्योगों

- रस्ट बैल्ट, मध्य अमेरिका का वह इलाका है, जो किसी जमाने में अमेरिका का "ओद्योगिक हब" था, जहां अमेरिका की अधिकतर "मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री" (ओद्योगिक उत्पादन) कार्यरत थी।
- पर, धीरे-धीरे बढ़ते वेतन आदि के कारण ये फैक्ट्रियां बंद हो गईं या मालिकों ने अपने प्लान्ट विदेश में शिफ्ट कर दिए।
- भारत पर, भारी टैरिफ लगाकर ट्रंप इस क्षेत्र के लोगों को सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं, कि ये कारखाने अब पुनः "रस्ट बैल्ट" में शिफ्ट हो जायेंगे तथा इस क्षेत्र में समृद्धि लौट आएगी।
- इसी प्रकार भारत पर दण्डात्मक टैरिफ लगाकर, ट्रम्प रूस व चीन को भी, कभी गरम, कभी नरम रुख दिखाकर बातचीत के लिए लुभाना चाहते हैं।

को चोट पहुँचाएँगे, लेकिन असली मकसद चीन, रूस और यहाँ तक कि अमेरिकी मतदाताओं को संदेश देना है, खासकर चुनावी साल से पहले।

ऊपरी तौर पर देखें तो ट्रंप का यह फैसला उनके लंबे समय से चले आ रहे "व्यापार राष्ट्रवाद" ("ट्रेड नैशनलिज़्म") का हिस्सा लगता है। उनका राष्ट्रपति काल, पहले और अब, दोनों में, यह नज़र आया है कि वे बहुपक्षीय नियमों को छोड़कर अमेरिका के विशाल उपभोक्ता बाज़ार को हथियार की तरह इस्तेमाल करने में हिचकिचाते नहीं। भारत के लिए यह समय बेहद खराब है। उसने बहुत मेहनत से छोटे-मोटे निर्यात से हटकर बेहतर उत्पादों पर ध्यान दिया था। अब छोटे और मझोले उद्योगों पर दबाव बढ़ सकता है और सालों की प्रगति पीछे जा सकती है। लेकिन कहानी सिर्फ़ इतनी नहीं है।

असल प्रश्न यह है कि भारत को ही क्यों चुना गया, जबकि वह क्वाड का साथी है, लोकतांत्रिक देश है और चीन का संतुलन भी बनाता है। जानकारों का कहना है कि यह भारत को सज़ा देने से ज़्यादा, दूसरों को खुश करने की रणनीति है। ट्रंप की सोच यह है कि व्यापारिक कदम असल में सौदेबाज़ी के पत्ते होते हैं।

भारत को निशाना बनाकर वॉशिंगटन शायद बीजिंग को संकेत दे रहा है कि वह एक मामले में चीन की बात मानने को तैयार है और दूसरे मुद्दों पर बातचीत का दरवाज़ा खुला रख रहा है। साथ ही यह मॉस्को को भी संदेश है कि अमेरिका उन देशों को दंडित करेगा जो पूर्व और पश्चिम दोनों से रिश्ते रखने की कोशिश कर रहे हैं। रूस से भारत के पुराने रिश्ते, खासकर ऊर्जा और रक्षा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मोदी ने फिनलैंड के राष्ट्रपति से फोन पर बात की

नयी दिल्ली, 27 अगस्त। फ़िनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्ज़ेंडर स्टब ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से टेलीफोन पर बात की और दोनों नेताओं ने विपक्षीय संबंधों की समीक्षा के साथ-साथ रूस यूक्रेन संघर्ष पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने रूस यूक्रेन संघर्ष के

- फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर स्टब ने रुस यूक्रेन वॉर के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के रुख का समर्थन किया। मोदी ने स्टब को भारत आने का न्यौता दिया।

शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत का समर्थन दोहराया।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि श्री मोदी के पास फ़िनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्ज़ेंडर स्टब की ओर से टेलीफोन आया था। राष्ट्रपति स्टब ने यूक्रेन में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)